

विचार

बांग्लादेश को माइनस में ले जा रहे हैं यूनूस

बांग्लादेश पूरी तरह से राह भटक गया है, इसीलिये वहाँ प्रदर्शन और हिंसा नहीं रुक पा रही है और न ही नेतृत्व, ऐसे निर्णय ले पा रहा है, जिससे बांग्लादेश शांति की ओर बढ़े और संप्रभु राष्ट्र बना रहे। बांग्लादेश में अब इस्लाइल को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका और आस-पास के शहरों में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आउटलेट भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गये, वहीं मोहम्मद यूनुस भी लगातार गलत निर्णय ले रहे हैं, वे चीन में शी जिनपिंग के सामने पूछ हिलाते दिखाई दिये और फिर चापलूसी की सभी हृदें पार करते हुये भारत की संप्रभुता से खेल गये, इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी बंद कर दी है, इससे पहले बैंकॉक में पिछले सप्ताह बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस से गलत बयानबाजी करने से बचने को कहा था, इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं बीपी गौतम....

बांग्लादेश में में प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया, जिससे उन्हें देश छोड़ना पड़ा। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथों में नेतृत्व चला गया लेकिन, मोहम्मद यूनुस भी असफल साबित हो रहे हैं। अब कटुरपंथियों द्वारा सोमवार से इस्त्राइल के विरुद्ध प्रदर्शन किये जा रहे हैं। गाजा में इस्त्राइली सेना का सैन्य अभियान चला, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है, इसके विरोध में बांग्लादेश में कटुरपंथी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्त्राइल से जुड़े उत्पादों का बायकॉट करने की भी आवाज उठाई जा रही है, साथ ही तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के आउटलेट्स पर भी हमला किया जा रहा है। बाटा, केएफसी और पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स को निशाना बनाया जा रहा है, इन पर इस्त्राइल से जुड़े होने की आशंका में कटुरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया।

बांगलादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर भीड़ हिंसक हो उठी। प्रदर्शनकारियों ने कई स्टोर्स में तोड़-फोड़ की और उनके स्टाफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की। बोगरा शहर में सैकड़ों की संख्या में छात्रों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस्टाइल के खिलाफ नारेबाजी की, इस दौरान इस्टाइली उत्पादों के बहिष्कार की मांग उठी और देखते ही देखते भीड़ ने बाटा के शोरूम पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस शोरूम पर पथर बरसाये, जिससे शीशे की दीवारें टूट गईं। हालांकि, इससे पहले कि भीड़ शोरूम में घुसकर कर्मचारियों को निशाना बनाती, कुछ कर्मियों ने हिम्मत दिखाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया।

योगी ने साकार किया राम को रोटी से जोड़ने का सपना

अपने यहां कहा जाता है, जिसने जन्म दिया वही रोटी का भी इंतजाम करेगा।

यह ऊपरवाले पर मुकम्मल भरोसे के साथ इस बात की ओर भी संकेत करता है कि अगर अपने इष्टदेवों से जुड़े स्थलों को सजा सवार दिया जाय। वहाँ आने

वाले पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर बुनियादी सुविधाएं

विकसित कर दी जाएं तो वहाँ भारी संया में रोजी रोजगार के अवसर स्थानीय और आसपास के लोगों को उपलब्ध होते हैं। यह राम को रोटी को जोड़ने जैसा है। तार प्रदेश के मुयमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सच साबित कर दिया। आज शिव की अविनाशी काशी और राम की अयोध्या पर्यटकों की आमद के मद्देनजर यहाँ के लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया बन गए हैं। कमोबेश

यही स्थिति अन्य तीर्थ स्थलों की भी है। तीरथराज प्रयाग में आयोजित

महाकुंभ में तो इसका चरमोत्कर्ष दिखा।



सरकार का अनुमान था कि करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में करीब 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु एवं पर्यटक शामिल होंगे, पर शामिल हुए 66 करोड़ से अधिक लोग। इनमें से बहुतों की मंजिल सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, काशी, अयोध्या, वनगमन के दौरान जहाँ भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित राम को निषादराज ने जहाँ उनको गंगा पार कराया था वह श्रृंगवरेपुर और वनगमन के दौरान राम ने मंदाकिनी के तट पर जिस चित्रकूट में सर्वाधिक समय गुजारा था, वह भी थी। कई लोगों ने विद्याचल स्थित मां जगदंबा के दरबार में भी हाजिरी लगाई।

अब एक पर्यटक ने औंसतन इस दैरान कितना खर्च किया। इस खर्च का कितना कितना लाभ इस सेक्टर से जुड़े स्टेकहोल्डर्स और स्थानीय लोगों को मिला। केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से में प्रयागराज के महाकुंभ और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और राममंदिर एवं अयोध्या के कायाकल्प पर हुए खर्च की तुलना में कितना लाभ हुआ, यह अर्थशास्त्र के जानकारों के लिए अनुमान विषय है। पर, यह निविवाद सच है कि पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद से लाभ में सब रहे। साथ ही इसने उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाओं का एक नया और बड़ा दरवाजा खोल दिया। क्योंकि, बहुसंख्यक समाज के रोम रोम में बसने वाले राम की अयोध्या, तीनों लोकों से न्यारी शिव की काशी और राधा कृष्ण की जन्म भूमि, ग्वाल बालों और गोपियों के साथ लीला के स्थल ब्रज उत्तर प्रदेश में हैं। इन सभी जगहों की संभावनाओं के महेनजर योगी सरकार यहां आने वालों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से लगातार काम भी कर रही

है। इसका नतीजा है कि पर्यटकों की आमद के हिसाब से उत्तर प्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2022 से ही घेरलू पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर बना हुआ है। सरकार के अंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 24 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 65 करोड़ हो गई। आठ वर्षों में 41 करोड़ की यह वृद्धि खुद में अभूतपूर्व है। स्वाभाविक है कि महाकुंभ के नाते 2025 एक नया रिकॉर्ड रचेगा। यह संख्या एक अरब का ऊपर तक जा सकती है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैंबरस ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 फीसदी से अधिक घेरलू यात्राएं धार्मिक स्थलों की होती हैं। धार्मिक पर्यटन आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए ऐसी सभी जगहों को बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं, सड़क और एयर कनेक्टिविटी, आने वालों की सुरक्षा और सेवा देनी होती है। यह सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी से कर रही है। यह सब यूं ही नहीं हुआ। इसकी पुष्टभूमि मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तभी से शुरू हो गई थी। तब अयोध्या जाना तो दूर की बात, कोई नेता अयोध्या का नाम तक नहीं लेना चाहता था उस अयोध्या में वह बार बार गए। हर बार उहोंने अयोध्या को विकास की बड़ी सौगात दी दीपावली के एक दिन पूर्व भव्य दीपोत्सव आयोजन कराया। इससे एक बार फिर देश-दुनिया में राम को मानने वालों का ध्यान अयोध्या की ओर गया। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम

कोर्ट का फैसला आने और मंदिर का शिलान्यास होने के बाद तो केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। मुख्यमंत्री की मंशा अयोध्या की दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी बनाने की है। इसे वे कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कह चुके हैं। उसी मंशा के अनुरूप अयोध्या में लगातार काम भी हो रहे हैं। काशी, प्रयाग, ब्रज क्षेत्र पर भी उनका इसी तरह फोकस है।

उल्लेखनीय है कि राम और रोटी का रिश्ता अदूर है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। राम मंदिर आंदोलन को धार देकर भाजपा ने इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख एजेंडा बनाया। करीब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जब राम मंदिर आंदोलन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा ही सत्ता में रही। सोने पर सुहागा यह कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ थे। यह वह पीठ है जिसका राम मंदिर आंदोलन से वास्ता करीब 100 वर्षों का है। योगी के दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिविजयनाथ, गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ और खुद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन के हर महत्वपूर्ण घटनाएँ समय मौजूद रहे। ऐसे में जनमानस के मन में यह बैठ गया है कि अयोध्या में श्रीराम को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम भाजपा ने किया। इस काम में गोरक्षपीठ की अहम भूमिका रही। बतौर पीठ के पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल इस कसौटी पर खरे उत्तर, बल्कि काशी, मथुरा, प्रयागराज सहित अन्य धार्मिक स्थलों के नियोजित विकास से अपने पद एवं दायित्व के अनुसार उसे विस्तार भी दिया। यह सिलसिला अभी जारी है।

क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी कब तक बनी रहेगी काँग्रेस

कांग्रेस अधिवेशन 2025 गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो गया है यह कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता है, बड़े से बड़े नेता इकट्ठा होते हैं पार्टी करते हैं चले जाते हैं दूसरे के बाल अधिवेशन से कुछ नहीं होगा आज मैं यह बोलने जा रहा हूं वह हो सकता है कांग्रेस के नेताओं को हजम ना होदू हालांकि सच तो बोलना होगादू सच्चाई यही है कि हर बार अधिवेशन होता है तमाम तरह के सुझाव निकलते हैं, मंथन होता है लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देतादू कांग्रेस बार-बार एक ही तरह की गलती दोहराती है, एक ही तरह के मुद्दे लेकिन सीख क्या लेती है अमल क्या करती है ज़मीन में कहीं दिखाई नहीं देतादू

राहुल गांधी बार-बार भाजपा को सर्विधान विरोधी बोलते हुए आरोप लगाते हैं और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे उठाते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा कहते हैं कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया जाता अगर बोलने नहीं दिया जाता तो आप सब सामूहिक इस्तीफा क्यों नहीं देते! अगर आप सामूहिक इस्तीफा देंगे तो सत्ता के चेहरे पर से नकाब उतर जाएगाय विपक्ष हमेशा ईवीएम का मुद्दा उठाती है लेकिन जब हार जाती है तब जब कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्य कांग्रेस जीत जाती है तब चुप हो जाती है दर-असल यही कमी दिखती है कि कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है एकत्रफा आप ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते

राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि हम जमीन से बदलाव करेंगे पार्टी को खड़ा करेंगेय कांग्रेस पार्टी में टिवटर चलाने वाले और सोशल मॉडिया पर आवाज उठाने वाले नेताओं का जमावड़ है लैकिन ज़मीन पर उतर कर काम करने वालों की भारी कमी हैद्य कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन लड़के ने बिल्कुल सही कहा है - हम मुस्लिम, दलितों में उलझ रहे और हमारा जो हमारा कोर बोटर ओबीसी हमेशा हमारे साथ रहा है, वह हमसे छटक गया हैद्य यह सच है जिसकी तरफ ओबीसी बोट होगा उसकी सत्ता होगी तो केवल अधिवेशन से सत्ता में वापसी कांग्रेस कर पाएगी ये वास्तविकता से विपरीत हैद्य कांग्रेस की तुलना में भाजपा का थिंकटैक बहुत ही सुदृढ़ हैद्य भाजपा एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की रणनीति में लग जाती है जबकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा यहाँ पिछड़ती है

तमिलनाडु में अगले करण में भाषा विवाद



कदा कई राज्य राष्ट्रीय सोच से अलग रुख अखिलायार करते रहते हैं। हाल के दिनों में इस कोशिश में पश्चिम बंगाल भी जुड़ा, जहां से राष्ट्रवादी विचारधारा को बल मिला। अरसे से कई मुद्दों पर अलग रुख अखिलायार करते वक्त तमिल राजनीति भारतीयता के अभिन्न अंग तमिल की अवधारणा और संविधान की सोच को दाकिना करनी पड़ी है।

दराकनार करता रहा ह।
तमिलनाडु में हिंदी विरोध 1935 में
डीएमके के वैचारिक उभार के साथ ही
शुरू हुआ। तब भी यह सोच राष्ट्रीय
युगबोध से अलग थी। तमिलनाडु में पहले
क्रांतिकारी सोच के नाम पर ब्राह्मण
विरोध की शुरूआत हुई, जिसका अगला
कदम हिंदी विरोध रहा। अब यह सोच
एक तरह से उत्तर भारत विरोध तक पहुंच
जाकी दै। दिलज़म्य यह है कि इसमें कई

सरकार ने करूणानिधि सरकार को कुछ ऐसी ही वजहों से बर्खास्त किया था। डीएमके करीब दो दशक से कांग्रेस की सहयोगी हैं, लेकिन अतीत में एक बार वह भी डीएमके की ऐसी सोच के चलते केंद्र को उभारना तमिलनाडु का आसान राजनीतिक फार्मूला रहा है। त्रिभाषण फार्मूले में हिंदी विरोध स्टालिन को सबसे आसान लगा और वे मैदान में कूद पड़े। जनसंख्या के लिहाजे से लोकसभा सीटों

की गुजरात सरकार को गिरा चुकी है। अभी चाहे हिंदी का सबाल हो या फिर रूपए के प्रतीक को बदलने की बात, डीएमके के रूख पर कांग्रेस ने फिलहाल चुप्पी साथ रखी है। ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस की स्थिति सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। अगर वह डीएमके का विरोध करती है तो उसे अपने स्थानीय समर्थकों के छिटकने का डर है और यदि समर्थन करती है तो उत्तर भारत में उसकी उम्मीदें बिखर सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने आक्रामक रूख अपना रखा है। रूपए का हिंदी प्रतीक बदलने का सबसे तेज विरोध तमिल मूल की निर्मला सीतारमण और राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई कर रहे हैं। उनका साथ उनकी पूर्ववर्ती तमिलसाई सौंदर्याराजन दे रही हैं। बीजेपी की कोशिश है, स्टालिन के हिंदी विरोध की हवा तमिल सोच के जरिए निकालने की है। इसका आधार जोहो कंपनी प्रमुख श्रीधर वेंकु हिंदी समर्थन में बह्यान देकर मद्देय करा चके हैं।

बवान दकर मुहया करा चुक ह।
अगले साल अप्रैल-मई में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2021 के चुनाव में दशकभर बाद डीएमके को सत्ता मिली थी। स्टालिन इसे ही बचाए रखने की जुगत में हैं। उत्तर और हिंदी विरोधी माहौल जिंदा रखकर स्थानीय भावनाओं समुदाय के एक हस्से का समझ बना ह कि उनकी सरकार का विरोध एक बिंदु पर राष्ट्रीय धारा के विपरीत हो सकता है। अब तमिलनाडु में भी लोग मिलने लगे हैं, जिन्हें हिंदी विरोध राजनीतिक शिगूफा लगता है। स्टालिन जिस तरह तेजी से एक के बाद एक मढ़े उछल रहे हैं

